

देश की अपारसना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष : 02

अंक : 12 :

जौनपुर, शुक्रवार 06 अक्टूबर 2023

सांख्य दैनिक (संस्करण)

पेज - 4

मूल्य : 2 रूपया

मोदी ने जोधपुर में करीब पांच हजार करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास

एजेन्सी
जोधपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को लगभग पांच हजार करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित शिलान्यास समारोह में श्री मोदी ने वीर दुर्गादास राठोड़ की इस वीर भूमि को नमन करते हुए कहा "आज मारवाड़ की पवित्र धरती जोधपुर में कई बड़े विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। गत नौ वर्षों में हमने राजस्थान के विकास के लिए जो निरंतर प्रयास किए हैं, उनके परिणाम आज हम सब अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। उन्होंने इन विकास कार्यों के लिए जनता को बधाई देते हुए कहा कि राजस्थान वो राज्य है, जहां प्राचीन भारत के गौरव के दर्शन होते हैं। जिसमें भारत के शौर्य, समृद्धि और संस्कृति झलकती है। कुछ समय पहले जोधपुर में जी-20 की जो बैठक हुई, उसकी तारीफ दुनियाभर के मेहमानों ने की। चाहे हमारे देश के लोग हों, या विदेशी पर्यटक हों, हर किसी की इच्छा होती है कि वो एक बार सूर्य नगरी जोधपुर देखने



के लिए जरूर आए। हर कोई रेतिले धोरों को, मेहरानगढ़ और जसवंत थड़ा को जरूर देखना चाहता है, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट को लेकर बहुत कुछ उसके लिए उत्कंठा रहती है। इसलिए, ये जरूरी है कि भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान, भारत के भविष्य का भी प्रतिनिधित्व करे। ये तभी होगा, जब मेवाड़ से लेकर मारवाड़ तक, पूरा राजस्थान विकास की बुलंदियों को छूए, यहाँ आधुनिक के इनफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो। उन्होंने कहा कि बीकानेर से बाड़मेर होते हुये जामनगर तक जाने वाला एक्सप्रेसवे कॉरिडोर, दिल्ली-मुंबई

एक्सप्रेसवे, राजस्थान में आधुनिक और हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है। भारत सरकार, आज राजस्थान में हर दिशा में, चहुँ दिशा में रेल और रोड समेत हर क्षेत्र में तेज गति से काम कर रही है। इसी साल रेलवे के विकास के लिए करीब-करीब साढ़े नौ हजार करोड़ रुपए का बजट राजस्थान को दिया गया है। ये बजट पिछली सरकार के सालाना औसत बजट से करीब 14 बुलंदियों को छूए, यहाँ आधुनिक के इनफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो। उन्होंने कहा कि बीकानेर से बाड़मेर होते हुये जामनगर तक जाने वाला एक्सप्रेसवे कॉरिडोर, दिल्ली-मुंबई

दशकों में वर्ष 2014 तक, राजस्थान में लगभग 600 किलोमीटर रेल लाइनों का ही बिजलीकरण हुआ। श्री मोदी ने कहा कि गत नौ वर्षों में तीन हजार सात सौ किलोमीटर से ज्यादा रेल ट्रेक्स का बिजलीकरण हो चुका है। इन पर डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेनें चलेंगी। इससे राजस्थान में प्रदूषण भी कम होगा और हवा भी सुरक्षित रहेगी। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत हम राजस्थान के 80 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिकता के साथ विकसित कर रहे हैं। हमारे यहाँ शानदार हवाई अड्डे बनाने का फैशन तो है, बड़े-बड़े लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन मोदी की दुनिया कुछ अलग है, जहाँ गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति जाता है, मैं उस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट से भी बढ़िया बना दूंगा और इसमें हमारा जोधपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आज रोड और रेल की जिन परियोजनाओं को शुरू किया गया है, उनसे विकास के इस अभियान को और गति लेगी। रेल लाइनों के इस दोहरीकरण से यात्रा में लगने वाला जो समय है, वो कम होगा, और सुविधा भी बढ़ेगी।

मुझे जैसलमेर-दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन और मारवाड़-खांबली घाट ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का भी सौभाग्य मिला है। और कुछ दिन पहले मुझे वंदे भारत के लिए भी मौका मिला था। आज यहाँ रोड के तीन प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास हुआ है। आज जोधपुर और उदयपुर हवाई अड्डों के नए पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है। इन सभी विकास कार्यों से इस इलाके की लोकल अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये राजस्थान में टूरिज्म सेक्टर को भी नई ऊर्जा देने में मदद करेंगे (साथियों, हमारे राजस्थान की मेडिकल और इंजीनियरिंग एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रही है। कोटा ने देश को कितने ही डॉक्टर और इंजीनियर्स दिये हैं। हमारा प्रयास है कि राजस्थान एजुकेशन के साथ-साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग की दृष्टि से भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला एक अच्छे से अच्छा हब बने। इसके लिए एम्स जोधपुर में ट्रोमा, इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर की एडवांस्ड सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है।



एजेन्सी
लखनऊ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा गुरुवार को उदयन सभागार में कौशांबी के विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। उप मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान एक क्लस्टर में 03 वर्ष पूर्ण कर चुकें ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारी को अन्य विकास खण्ड में तैनात करने के निर्देश दिये। उन्होंने 03 वर्ष पूर्ण कर चुकें लेखपालों को अन्य तहसील में तैनात करने तथा एक थाने में 02 वर्ष पूर्ण करने वाले दरोगा सिपाही को अन्य सर्किल क्षेत्र अर्द्ध से अर्द्ध हब बने। इसके लिए एम्स जोधपुर में ट्रोमा, इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर की एडवांस्ड सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है।

लाभान्वित किया जाय तथा विकास कार्यों को तेजी से पूर्ण कराया जाय, ताकि जनपद का सर्वांगीण विकास तेजी से हो सके। उन्होंने ओवरलॉड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। उप मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान एक क्लस्टर में 03 वर्ष पूर्ण कर चुकें ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारी को अन्य विकास खण्ड में तैनात करने के निर्देश दिये। उन्होंने 03 वर्ष पूर्ण कर चुकें लेखपालों को अन्य तहसील में तैनात करने तथा एक थाने में 02 वर्ष पूर्ण करने वाले दरोगा सिपाही को अन्य सर्किल क्षेत्र अर्द्ध से अर्द्ध हब बने। इसके लिए एम्स जोधपुर में ट्रोमा, इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर की एडवांस्ड सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है।

जयपुर जिले के 19 विधानसभा क्षेत्रों पर 50 लाख से ज्यादा

मतदाता करेंगे मतदान

एजेन्सी
जयपुर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जयपुर जिले की 19 विधानसभा क्षेत्रों में 50 लाख 47 हजार 219 मतदाता आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मतदाधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि इनमें 26 लाख 36 हजार 25 पुरुष मतदाता एवं 24 लाख 11 हजार 194 महिला मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रारूप प्रकाशन की तिथि तक 18-19 वर्ष की आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 1 लाख 54 हजार 644 थी जो कि अंतिम प्रकाशन के समय बढ़कर 1 लाख 96 हजार 834 हो गई है। इस प्रकार 18-19 वर्ष की आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या में 42 हजार 190 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि द्वितीय पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जयपुर जिले में कुल 54 हजार 189 आपत्तियां स्वीकार की गईं।

हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं, हाई कोर्ट में अहम सुनवाई शुक्रवार को

एजेन्सी
रांची। जमीन घोटेला मामले में पूछताछ के लिए ईडी के पांच समन के बावजूद उपस्थित नहीं होने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिट पिटिशन पर झारखंड हाईकोर्ट में 6 अक्टूबर को अहम सुनवाई होगी। सोरेन के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश द्वारा मामले को मेशन किए जाने के बाद उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई की तारीख तय की है। सोरेन की याचिका में ईडी की ओर से जारी समन को कानून के खिलाफ बताया गया है। वहीं, पीएमएलए एक्ट की विभिन्न धाराओं की वैधता को भी चुनौती दी गयी

है। गौरतलब है कि जमीन के कागजात में हेराफेरी और खरीद-बिक्री में हेराफेरी के कारण रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, जमीन कारोबारी विष्णु अग्रवाल और अमित अग्रवाल समेत कई आरोपी जेल में हैं। इसी के बाद ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समन दर समन जारी कर पूछताछ के लिए ईडी के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रोड स्थित कार्यालय में बुलाया था, लेकिन मुख्यमंत्री किसी भी तारीख पर उपस्थित नहीं हुए। हालांकि उन्होंने ईडी के हर समन के बाद लिखित तौर पर जवाब भेजा। उन्होंने हर समन के जवाब को ईडी की ओर से चौथा समन जारी कर 23 सितंबर को आने को कहा था। वहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील मुकुल रोहतगी को कोर्ट ने कहा था।

एजेन्सी
नयी दिल्ली। छात्रों के स्कूल ड्रॉप आउट की समस्या से निपटने के लिए एक खास स्कॉलरशिप राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति शुरू की गई है। यह छात्रवृत्ति खास तौर पर इसलिए डिजाइन की गई है ताकि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई न छोड़ें। छात्रवृत्ति की राशि 12,000 रुपए प्रति वर्ष है।

इस योजना के तहत एक लाख छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, वर्ष 2023-24 के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) पर छात्रवृत्ति के आवेदनों की ऑनलाइन जमा या पंजीकरण की प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2023 को शुरू हो गई। राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति (एनएसएमएसएस) योजना के तहत कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या को कम करने के



के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है। एनएसएमएसएस छात्रवृत्ति डीबीटी मोड के बाद सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द्वारा सीधे चयनित छात्रों के बैंक खातों में वितरित की जाती है। यह केंद्र सरकार की योजना है। ये छात्र जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से आय प्रति वर्ष 3,50,000 रुपए से अधिक नहीं है, वे छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के पात्र हैं।

छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए चयन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए छात्रों के पास सातवीं कक्षा की परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष बंद होना चाहिए (एएससी, एसटी छात्रों के लिए 5 प्रतिशत की छूट)। छात्रवृत्ति आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर सत्यापन के बाद स्कॉलरशिप स्क्रीन हटाया जाएगा। एनएसएमएसएस (एनएसपी) पर उपलब्ध कराया गया है। यह छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं

चकबंदी विभाग के एक दर्जन लापरवाहों पर गिरी गाज सीएम योगी ने मामले में लेटलतीफी, लापरवाही और अनियमितता पर लिया गया एक्शन, कौशांबी के 6 को किया निलंबित



एजेन्सी
लखनऊ। यूपी के चकबंदी विभाग में संबंधी मामलों के निपटारे में लेटलतीफी, लापरवाही, अनियमितता पर मुख्यमंत्री की सख्त नाराजगी का असर दिखने लगा है। सीएम योगी के कड़े रुख के बाद चकबंदी विभाग में बड़े स्तर पर आधा दर्जन जिलों के चकबंदी अधिकारी से लेकर लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई की गयी। चकबंदी आयुक्त ने सीएम योगी के निर्देश के बाद गुरुवार को कौशांबी

में तिहरे हत्याकांड में पट्टे की भूमि विवाद में लापरवाही पर चकबंदी अधिकारी समेत 6 लोगों को निलंबित कर दिया है जबकि कुल एक दर्जन लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। इनमें निलंबन से लेकर एकआईआर और यहां तक कि नौकरी से बर्खास्तगी की कार्रवाई भी की गई है। वहीं चकबंदी आयुक्त की ओर से पिछले एक माह में एक दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। मुख्यमंत्री

योगी आदित्यनाथ ने 16 सितंबर को एनेक्सी में राजस्व की समीक्षा बैठक में लापरवाही और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये थे, जिसके बाद विभागीय स्तर पर उनकी लिस्ट तैयार की गयी। वहीं सीएम योगी से हरी झंडी मिलते ही ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। जानकारों की मानें तो अभी और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने बताया कि सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि कौशांबी में तिहरे हत्याकांड में पट्टे की भूमि विवाद में लापरवाही पर चकबंदी अधिकारी मिथिलेश कुमार, सहायक चकबंदी अधिकारी अफजाल अहमद खां, तीन चकबंदी लेखपाल शिवेश सिंह, शीलवंत सिंह, रवि किरन सिंह और चकबंदीकर्ता

राम आसरे को निलंबित कर दिया है वहीं अनियमितता एवं अनुशासनहीनता पर चकबंदी अधिकारी देवराज सिंह की सेवा समाप्त कर दी गयी है जबकि एटा के सहायक चकबंदी अधिकारी सतीश कुमार को पदावन्त कर रहे हुए मूल वेतन पर नियुक्त किया है। इसी तरह चकबंदी योजना तैयार करने में नियमों का उल्लंघन करने एवं लापरवाही पर शामिल, हरदोई के सहायक चकबंदी अधिकारी अनंजनाल सिंह और गजराज को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं चकबंदी में गडबड़ी की शिकायत पर गठित जांच निदेशालय की टीम की संतुति पर मऊ के चकबंदीकर्ता तथा चकबंदी लेखपाल को निलंबित करने के निर्देश दिये गये हैं। वहीं बस्ती और हरदोई के चकबंदी अधिकारी शरदचन्द्र यादव और प्रेम प्रकाश भारती के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गयी है।

दिल्ली शराब केस: आप नेता संजय सिंह कोर्ट में पेश, अदालत ने ईडी ने पूछा- मोबाइल जब्त को कस्टडी की जरूरत क्यों?

एजेन्सी
नयी दिल्ली। दिल्ली के राजज एवेन्स्यु कोर्ट में ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को गुरुवार को पेश किया। ईडी ने कोर्ट से संजय सिंह की 7 दिन की हिरासत में लेने की मांग की है। इस पर कोर्ट में बहस जारी है। कोर्ट ने ईडी से पूछा है कि जब मोबाइल जब्त है तो कस्टडी की क्या जरूरत है। ईडी ने कहा कि हमने दो-तीन लोगों से आमना-सामना कराना है। जांच एजेंसी ने कहा कि सबूतों के आधार पर पूछताछ करनी है। दो तीन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। कोर्ट ने फिर सवाल किया कि जब सबूत थे तो गिरफ्तारी में इतना टाइम क्यों लगा? कर उत्तर प्रदेश प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने

एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि सरकार को ये लगता है कि जो भी उनके खिलाफ को पेश किया। ईडी ने कोर्ट से संजय सिंह की 7 दिन की हिरासत में लेने की मांग की है। इस पर कोर्ट में बहस जारी है। कोर्ट ने ईडी से पूछा है कि जब मोबाइल जब्त है तो कस्टडी की क्या जरूरत है। ईडी ने कहा कि हमने दो-तीन लोगों से आमना-सामना कराना है। जांच एजेंसी ने कहा कि सबूतों के आधार पर पूछताछ करनी है। दो तीन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। कोर्ट ने फिर सवाल किया कि जब सबूत थे तो गिरफ्तारी में इतना टाइम क्यों लगा? कर उत्तर प्रदेश प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने

की शुरुआत में दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि ईडी पिछले 15 महीनों से कथित दिल्ली उत्पादक शिल्क नीति घोटेला की जांच कर रही है, लेकिन सबूत पेश करने में विफल रही है। उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए यह बताने को कहा कि श्री सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी में कितना पैसा बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि एजेंसी को आगे आना चाहिए और देश को इसके बारे में बताना चाहिए। आतिशी ने कहा, "अगर आपके (भाजपा) पास एक पैसा का भी सबूत है तो वह देश के सामने पेश करें या फिर राजनीति छोड़ दें। भाजपा पर निशाना साधते हुए दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ गुरुवार को राजधानी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। आज दिन

